[श्री रणधीर सिंह]

को पया दें, पांच हजार रुपया दें—जो कि ट्यूब-वेल बनाने में लगता है ।

यह एक ऐसी बात है, जिसकी वजह से मेरे दिल में दर्द होता है । जब वह पांच हजार रुपया ट्यूब-वेल के लिये मांगता है, और हुकूमत की तरफ़ से इन्स्ट्रक्शन्ज हैं कि तीन महीने में ट्यूब वेल का रुपया दिया जाय, तीन तीन साल तक उसको ट्यूब-वेल का रुपया नहीं दिया जाता । उस पांच हजार रुपये में से दो हजार रुपये किसान को रिश्वत के देने पड़ते हैं— नीचे से लेकर ऊपर तक । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि मैं अभी एक महीने तक अपने सारे हल्के में घूम कर आया हूं, 100 गांवों के किसानों ने रोते हुए कहा कि हम देश को निर्भर बनायेंगे, देश की पैदावार को बढ़ायेंगे, लेकिन जो चीज चाहिये वह तो दो । हर किसान बिजली और रुपया चाहता है, अगर ट्यूब-वेल के लिये उसको रुपया दे दें, उस के लिये पानी का बन्दोबस्त कर दें, तब आप देखना कि इसका कितना शानदार नतीजा निकलता है ।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान अब इन मण्डियों की लूट-खसोट को बरदाश्त नहीं करेगा । आपने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन बनाई है, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाइये । जो अनाज किसान पैदा करता है, उसका सही रिटर्न उसको मिलना चाहिये । मैंने अन्दाजा लगाया है कि अगर एक मन गेहूं पैदा करने में किसान का 45 या 46 रुपया लगता है, तो वह चाहेगा कि जो रुपया उसका लगा है, उस का ठीक रिटर्न उसको मिले । स्टेट ट्रेडिंग की मारफत आप किसानों की जिन्स को लें, उसको कुछ रुपया फस्ल के मौके पर दें, उसके लिए रियूमनरेटिव प्राइस मुकर्रर कर दें, जितना पैसा उसका लगता है, उससे ज्यादा पैसा उसको दें, ताकि उसकी मेहनत का उसको सही रिटर्न मिल सके और अपनी पैदावार को बढ़ाने में उसका हौसला आफजाई हो सके ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें एक मियाद मुकर्रिर करनी चाहिये । डा० लोहिया ने भी आज इस बात का जिक्र किया है कि हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, जैसे हमारे पांच साला प्लान हैं, उसी तरह से इरिगेशन देने के लिये हमें एक पांच साला या सात साला प्लान बनाना होगा । जिसके मुताबिक पांच साल के अन्दर एक एक चप्पा जमीन को पानी देना होगा, अगर हम जमीन को पानी दे सके तो आप देखेंगे कि हमारी उपज किस तेजी से बढ़ती है ।

एक बात खास तौर से मैं फर्टीलाइजर के बारे में कहना चाहता हूं । फर्टीलाइजर, बीज और बिजली— ये किसान के मीडियम आफ़ प्रोडक्शन हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue his speach tomorrow.

17.28 hrs.

NATIONAL FOOD BUDGET*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय खाद्य बजट के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया था और जो उस का उत्तर आया है, उस को लेकर मैं यह बहस उठाना चाहता हूं । आपको याद है कि 30 मई को इस सदन में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में कुछ सवाल पूछे गये थे, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य बजट का सवाल भी पूछा गया था तथा सरकार की ओर से निम्न उत्तर दिया गया था—

*Half-An-Hour Discussion.

"It was recognised that the tentative national food budget placed before the Conference had some limitations on account of the imperfect data available relating to production, consumption etc. It was, therefore, felt that in order to meet the difficult situation during the year it would be necessary to proceed on an *ad hoc* basis."

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह मांग की गई थी कि राष्ट्रीय खाद्य बजट का जो मस्विदा उन्होंने मुख्य मंत्री सम्मेलन के सामने रक्खा था वह सदन की टेबुल पर भी रक्खा जाय लेकिन जान बूझ कर खाद्य मंत्री ने यह सदन की टेबुल पर नहीं रक्खा। किसी भी मंत्री का यह फर्ज होना चाहिए कि सदन जो जानकारी मांगता है वह जानकारी उन को तत्काल दें। वैसे तो स्वयं ही देनी चाहिये और मांगने पर तो बिलकुल इंकार नहीं करना चाहिये। लेकिन यहां अजीब हाल है? इसमें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है फिर क्या वजह है कि मंत्री महोदय अपने आंकड़े और अपना मस्विदा सदन के सामने रखने के लिये तैयार नहीं हैं? मेरा अपना अंदाज है अनुमान है कि वह इसलिये नहीं रखना चाहते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य बजट का उन्होंने जो आधार बनाया था उसमें इतनी विषमता, असमानता और अमानुषता थी कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है सदन के सामने आने की। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास वह कागज नहीं है मैं कोशिश कर रहा हूं प्राप्त करने की अगर मुझको मिल जाएगा तो मैं स्वयं रख दूंगा। लेकिन मुझे खबर मिली है कि उस में इन लोगों ने कहा है कि कुछ राज्यों के आदमी जो हैं वह साल में 108 किलो या 112 किलो अनाज खाकर जिंदा रह सकते हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिनको 120 मिलना चाहिए, 130 मिलना चाहिए और कुछ राज्य शायद ऐसे भी हैं कि जहां 140 किलो देने की बात कही गई है। जैसा कि हमेशा होता है माननीय खाद्य मंत्री जिस इलाके से आते हैं वह बड़ा अभागा इलाका है, फी व्यक्ति राज्य वार आमदनी का जहां तक सवाल है हिन्दुस्तान में सब से गरीब इलाका बिहार का इलाका है। सरकार के पास मैं ने कई दफे कहा कि तीन योजनाएं खत्म हो चुकीं चौथी योजना आप बना रहे हो लेकिन अभी तक राज्यवार फी व्यक्ति आमदनी क्या है उसका अभी तक पता नहीं। कई सवाल मैंने पूछे मगर कह दिया गया कि योजना मंत्रालय अध्ययन कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इसका कब और कैसे पता चलेगा? अगर आप ठीक योजना बनाना चाहेंगे तो किस राज्य की क्या आवश्यकता है, कहां गरीबी ज्यादा है, स्वास्थ्य का इंतजाम सबसे खराब कहां है, शिक्षा की कमी कहां है इन चीजों का पता लगाना चाहिए। जब तक सरकार स्वयं इसके बारे में आंकड़े इकट्ठे कर के सदन के सामने नहीं रखती है और अपनी आर्थिक योजना भी उसी के आधार पर नहीं बनाती है। देश में संतुलित विकास नहीं हो पायेगा।

इसी तरह फी व्यक्ति अनाज की उपलब्धि पिछले पांच वर्षों में क्या रही उस के बारे में भी हमने कई सवाल पूछे थे लेकिन अखिल भारतीय औसत तो ये हर साल बतलाते हैं कि इस साल इतनी उपलब्धि रही, पिछले साल इतनी थी और कितनी कम हो गयी है। अखिल भारतीय औसत आंकड़े तो आ रहे हैं। लेकिन राज्यवार आंकड़े नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या हिन्दुस्तान के जो दूसरे पिछड़े हुए इलाके हैं उन में अनाज की फी व्यक्ति उपलब्धि अखिल भारतीय औसत है उस से दो या डेढ़ या ढाई आउंस कम है। उस के बारे में तथ्य और आंकड़े सदन के सामने नहीं रक्खे गये हैं। फी व्यक्ति आमदनी के औसत के आंकड़े शायद इनके पास उपलब्ध नहीं है लेकिन खोजनाफल की जो संस्था

[श्री मधु लिमये]

है उस ने दो दफे इसके बारे में आंकड़े प्रकाशित किये हैं और इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 15 वर्षों में राज्यवार फी व्यक्ति जो आमदनी है, पर कैप्टा इनकम स्टेटवाइज उसमें जो अन्तर है, विषमता है वह कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। फिर मैं जिक्र करना चाहता हूं कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, इन राज्यों की आमदनी और आंध्र, महाराष्ट्र के भी कुछ ऐसे जिले हैं और दूसरे इलाकों के भी जिले हैं जिनकी कि आमदनी बहुत कम है। पश्चिमी बंगाल चूंकि उसमें कलकत्ता है, उसी तरह पंजाब है जहां अंग्रेजों के जमाने से विकास पर पूंजी लग रही है, नहर आदि को लेकर महाराष्ट्र चूंकि उसमें बम्बई है, मैं देहाती इलाकों की बात नहीं कर रहा हूं फी व्यक्ति औसत आमदनी बिहार से दुगुनी है। इनके बारे में कोई आंकड़े नहीं दिये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और दुःख की बात है। मैं कभी कभी अपने को भी दोष देता हूं कि दो साल हो गये मेरे ध्यान में यह बात कैसे नहीं आई कि आप ने खेती के दाम निश्चित करने के लिए एक कमीशन बनाया। उस की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह मेरे पास है। यह करीब करीब दो साल पहले की रपट है। उस के बाद मेरा खयाल है कि 10–11 रपट आ चुकी हैं। इन में से एक भी आप ने प्रकाशित नहीं की है। अभी गेंहूं के बारे में, जूट के बारे में रपट आई है। यह रपट भी आप ने प्रकाशित नहीं की है। मैं आज खाद्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि पहली रपट प्रकाशित करने के बाद आज तक इन्होंने बाकी रपटों को क्यों नहीं प्रकाशित किया? सारांश तक नहीं है। मैं समझता हूं कि उस का कारण यह है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने अपनी विभिन्न रपटों में सरकार की खाद्य नीति की घोर आलोचना की है। वह डरते हैं कि उन्होंने ही जो कमिशन बनाया जो रपट है, जो सिफारिशें हैं उनके प्रकाशित होने से सरकार को नुकसान पहुंचेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खाद्य बजट इसलिए नहीं बन रहा है कि खाद्य के बारे में इनकी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। कल ही एक सवाल यहां पर पूछा गया कि इनकी जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देने की नीति है, जिसके कारण इधर का अनाज उधर नहीं जाता, उसका क्या नतीजा हो रहा है? ऐसा सवाल पूछा गया था। मेरा खयाल है कि देसाई साहब का यह सवाल है। उस में उन्होंने पूछा है कि विभिन्न राज्यों में जो अगल बगल में हैं, उनमें उसी अनाज के दाम क्या हैं? एक बड़ी विचित्र चीज मिलती है और खुद सरकार ने जवाब में स्वीकार किया है कि यह जो मोटे अनाज का मई महीने में थोक दाम 170 रुपये क्विंटल था और उसी का दाम महाराष्ट्र में साढ़े 68 रुपये था। इसी तरह मैं पंजाब और दिल्ली का भी जिक्र करूं। अनाज के दाम पंजाब में 77 रुपये है दिल्ली में 57 रुपये है। यह ज्यादा आंकड़े मैं देना नहीं चाहता लेकिन बात बिल्कुल साफ है कि इन्होंने देश में जो कई पाकिस्तान पैदा किये हैं उस का यह नतीजा हुआ है कि आज हिन्दुस्तान के कई इलाके चूसे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि खाद्य के बारे में वह बुनियादी बातों पर सोचें। उन से एक दफा पूछा गया कि खाद्य के बारे में हिन्दुस्तान में व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है, तो उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया है। जब उन से आवश्यकता के बारे में पूछा गया तो वह यह जवाब देते हैं :

> "There is no uniform daily requirement of foodgrains per person even in India. The requirement of foodgrains by a person depends on his income."

यानी खाद्य की आवश्यकता आमदनी पर निर्भर करती है । उपलब्धि या खरीदने की शक्ति आप कहेंगे उस पर निर्भर करती होती तो मैं मानता । लेकिन हमारा एक साधारण औसत तो निकालना चाहिये कि कम से कम जिन्दा रहने के लिये, ठीक तरह से, हिन्दुस्तान में गल्ले की इतनी आवश्यकता है। हर एक रोज किसी भी व्यक्ति को इतना अनाज देने की जिम्मेदारी, मैं समझता हूं, सरकार की और शासन की है । शासन से मेरा हर्गिज यह मतलब नहीं है कि केवल केन्द्रीय सरकार की । उस में मैं राज्य सरकारों को भी समाविष्ट करता हूं । लेकिन जब इस किस्म के ऊट पटांग जवाब आते हैं तो उस का मतलब होता है कि खाद्य मंत्री की राय में जो गरीब लोग हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ज्यादा मर रहे है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में—यही लोग मर रहे हैं पिछड़े हुए क्षेत्रों और वर्गों के जिन की आमदनी कम है—उन को अधिक खाद्य की आवश्यकता नहीं है । अगर यह कहते कि जितनी आवश्यकता है उतना नहीं मिल रहा है और उसे दिलाने के लिये हम राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं, एक राष्ट्रीय बजट बना रहे हैं तो उन की बात मानता ।

आप की मार्फत जो जानकारी मैंने मांगी है वह मंत्री महोदय देने की कृपा करें और अपनी राष्ट्रीय खाद्य नीति क्या है, उस की मोटी मोटी बातें क्या हैं, यह सदन के सामने रखने का कष्ट करें ।

Shri R. K. Amin (Dhandhuka): Sir, I would like to ask one question.

Mr. Deputy-Speaker: According to rules only those who have intimated to me their desire to put a question will get a chance to do so. Only one question is allowed to be put by a Member. I will be very strict about the rules. It is a half-hour-discussion. He wants further clarification and information regarding a question where he was not satisfied with the reply.

Shri S. S. Kothari (Mandsaur): Sir, I have to build up the background.

Mr. Deputy-Speaker: If everybody starts building up the background this discussion will not be over in half-an-hour.

Shri S. S. Kothari: Sir, it is not even second-class-citizenship, my name is there on the motion.

Mr. Deputy-Speaker: Because your name is there, you have no right.

Shri S. S. Kothari: Then these rules should be changed.

Mr. Deputy-Speaker: That is another matter.

श्री मधु लिमये : इसीलिए मैंने कम समय लिया है। उन्हें दो चार मिनट तो दीजिये। वह हस्ताक्षर करने वालों में हैं।

Mr. Deputy-Speaker: There are several other people who have intimated their names to me.

Shri Srichand Goel (Chandigarh): Sir, it has been the practice in this House....

Mr. Deputy-Speaker: I have been here for the last ten years. I am following the rules. He may put his question.

Shri Srichand Goel: I only want to remind you of the practice that we have been following in this House.

Mr. Deputy-Speaker: I know the practice in this House. Let not the hon. Member take the time of the House over that.

श्री भवानी सिंह (देहरादून) : सवाल यह है कि जिन्होंने इस तरह का क्वेश्चन दिया है, जिन्होंने इस तरह का नोटिस दिया है, कम से कम उन को समय मिलना चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Shri Kothari may put his question.

Shri S. S. Kothari: In view of the recent Hare-up in the West Asian situation, the whole national food budget which, as Shri Limaye said, has not been brought before the House, would have to be amended. The Food Minister has to amend it and present it before the House. Because the ships will have to be diverted along the Cape of Good Hope, it would mean a delay of about 15 days. What is your assessment of your being able to fulfil the demands of the various States and the amount of foodgrains that you are going to supply to them?

Mr. Deputy-Speaker: It does not arise out of this.

Shri S. S. Kothari: If it does not arise, what else will arise? The whole national food budget has to be abandoned. This budget is affected; that is a basic and fundamental point. If we ignore that, what is the use of discussing the national food budget?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): The situation which the hon. Member is referring to was not in existence when he sent his notice.

Shri S. S. Kothari: But the current situation has to be taken into account.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से विशेष वर्गों के लोगों के लिये खाने की मात्रा अधिक है तो क्या उसी तरह से खाद्य का वितरण हो रहा है ? सैनिक, असैनिक और अर्सैनिक कर्मचारियों, खासकर पुलिस को जो भोजन दिया जाता है अथवा संसद् सदस्यों को, इस की मात्रा क्या अधिक है औरों की अपेक्षा ? यदि हां, तो इस में कितना अन्तर है ?

श्री जगजीवन राम : इस का बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है

Shri E. K. Nayanar (Palghat): The Government of India has not chalked out a national plan for the nearest future. Some ten years back the Food grains Inquiry Committee made some suggestions. One of the suggestions was that until there is social control over the wholesale trade we shall not be in a position to bring about stabilisation of the wholesale prices in foodgrains. That has not been taken into account. Following this recommendation by the Foodgrains Inquiry Committee in 1957, the National Development Council decided in November 1958 that the State should take over the wholesale trade in foodgrains.

Mr. Deputy-Speaker: Please come to your question.

Shri E. K. Nayanar: Even with the import Government have a national food plan. If Government procures all the surplus food in India, Government can give at least 15 ounces *per capita* per day. That has been explained by the well-known economist Dr. Raj in January last year. 15 ounces *per capita* per day is the production needed to supply every Indian reasonable food. In no year in the last decade has the *per capita* availability of foodgrains fallen below this level and except in two years, 1951-52 and 1952-53 it would have been possible to ensure this from domestic production. That is why I am asking if Government is prepared to take over all the surplus and the responsibility of the wholesale trade, as recommended by the National Development Council in 1958.

श्री रवी राय (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि दो फसलों के बीच में जो खाद्यान्न का भाव बढ़ता रहता है क्या वह 16 प्रतिशत के अन्दर ही रहेगा, उस से अधिक तो नहीं बढ़ेगा ? क्या इस की सूचना मंत्री महोदय हाउस में देंगे ?

Shri Sequeira (Goa, Daman and Diu): The hon. Minister stated in his reply that the food budget would be finalised after the Chief Ministers' Conference. I would like to ask of him when is it likely now to be finalised. He also said that it was difficult to finalise the budget because the the estimate of consumption and the movement on private account were not adequate. What arrangements have been made to improve the collection of this data? What progress has been made since this question was answered? I also wish to ask him whether any steps have been taken to mobilise public opinion in favour of a national food budget? Has the radio been used, has any other mass media of communication been used? If not, are they proposed to be used and when?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome this opportunity to discuss the problem raised in connection with the National Food Budget. Mr. Madhu Limaye is a very enthusiastic parliamentarian and all of us have great respect for him. But the way in which he raisd today's discussion, I do not think, there is much relevance in the point made out by him.

. . . . .

First of all, I shall be thankful to him if he brings to my notice that when Q. 20 was being discussed he made a demand that some documents which were circulated to Chief Ministers be placed on the Table of the House.

श्री मधु लिमये : मांग की गई थी । उस वक्त नहीं की गई थी बाद में की गई थी । मैं निकाल कर दे सकता हूं । उसका जवाब आपने दिया था कि ये टैंटेटिव है नहीं रखेंगे । अगर रखने के लिए तैयार हैं तो झगड़ा खत्म हो जाएगा । लेकिन उस वक्त आपने इन्कार किया था ।

Shri Annasahib Shinde: I am speaking with reference to Q. 20.

श्री मधु लिमये : मैं यह नहीं कहता हूं कि तब यह मांग की गई थी । लेकिन सदन में इस सम्बन्ध में मांग की गई थी । आपने "न" कहा था । इसलिए मुझ को कहना पड़ा ।

Shri Annasahib Shinde: This discussion is strictly confined to Q. 20.

श्री मधु लिमये : क्या सदन में इसी के सम्बन्ध में जो कहा गया है उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है ? इसके सम्बन्ध में एक बार जब मांग की गई थी तो उसके बारे में नहीं कहा गया था ? इस सदन में, इस सम्बन्ध में जो हुआ है, उसका उल्लेख करने का क्या मुझे अधिकार नहीं है ?

Shri Annasahib Shinde: The notice that had been given....

श्री मधु लिमये : आप तो मेरे भाषण को ही काट रहे हैं इरेलेवेंट कह कर । जो इस सदन में घटित हुआ है, उसके बारे में मैं कह रहा हूं ।

Shri Annasahib Shinde: I am not yielding. When he expressed views with which I disagree, I did not interrupt him at all.

श्री मधु लिमये : श्री जगजीवन राम जी ने कहा था कि हम नहीं रखेंगे ।

Shri Annasahib Shinde: The hon. Member need not interrupt me. I did not interrupt him when he was speaking.

Shri Sonavane (Pendherpur): Sir, is it a quarrel or a debate? There should be some control....

श्री मधु लिमये : पहले अपने मंत्रियों को आप कंट्रोल करें । हम को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं ? उनको पहले कंट्रोल करें ।

Shri Annasahib Shinde: Let us take it in a sportsmanlike manner. There is nothing unparliamentary ; we should give and take.

Sir, this National Food Budget was to be discussed in the Chief Ministers' Conference. Of course, some tentative documents were circulated to Chief Ministers for the discussion. We have never expressed the view that the facts mentioned in the documents which were circulated or the figures mentioned there in were final figures. They were only suggestions for discussions. In fact, the hon. Minister of Food and Agriculture who conducted the proceedings of the Conference pointed out in the Conference that there were certain limitations because of imperfect data in regard to availability of foodgrains in the country. For instance, it has already been mentioned that reliable estimate of actual levels of consumption on Statewise basis are not available in the absence of scientific and comprehensive surveys on food consumption. Moreover, all relevant data regarding inter-State inflow or outflow of foodgrains, particularly movement by road on private account are not available. Also, data on changes in stocks with producers and traders are not available. The usual allowance made for feed, seed and wastage is 12½ per cent of the total production in every State and such an allowance differs from grain to grain. Consumption patterns are influenced by the levels of income and changes therein over time obtaining in different States. The *per capita* consumption of cereals also depends on the extent to which subsidiary foods like, potatoes, sweet potato and tapioca supplement cereals intake.

Taking all these facts into consideration, the hon. Minister of Food and Agriculture suggested that it may not be possible to proceed on the basis of tentative suggestions that were mentioned in the documents circulated to the Chief Ministers. Perhaps, the Chief Ministers also had some difficulty about it and the National Food Budget was not finalised. I do not understand why the hon. Member should be so much concerned about it. Had we taken some decision on the basis of it or had we committed some mistake, perhaps, the hon. Member would have been right in making a complaint or raising a discussion here.

May I draw the attention of the hon. House to the fact that consumption pattern and *per capita* availability of food is a very complex matter all over the world? I have got the figures of F.A.O. for various countries. Considerable studies have been made. They also indicate considerable variations. In the case of some countries, the figures is 65 kgs. per year while in respect of some other countries, the figure shown is 223 kgs. per year. The variations is so wide, from country to country, and, similarly, it must be the case in respect of our country. The per-head availability of food must be different not only from State to State, but even within a State; for instance, take the case of North Bihar where the population pressure is too much, the land-man ratio is very high; even there, the consumption pattern must be different from the consumption pattern round about Jamshedpur or Calcutta.

I know something of Maharashtra. There, some studies were conducted in regard to consumption pattern of food, comparing the per-head availability of food, the consumption pat-

tern, in Bombay city with that in the drought affected areas, the areas which are subject to recurrent famines. I myself come from an area which is subject to recurrent famine. The studies conducted indicated that the disparity between the consumption pattern round about Bombay and Poona and the consumption pattern in rural areas which are subject to recurrent famine was very wide. One fails to believe that there could be so much of disparity. As is well known, a large section of the population is poor; they have no purchasing power and that is perhaps the reason for this disparity. I have a document here, the Third World Food Survey, an authoritative publication on behalf of F.A.O. It also says that the pattern of consumption of cereals is different from region to region and within a region also. This is an expert study. May I submit for the information of the hon. House that our endeavour should be to remove this disparity, but that is not so easy; it will take quite some years and it could be brought about perhaps only by increasing agricultural production, by raising the standard of living, but even then I do not know whether it can be done. I do not know of any country in the world where consumption patterns are on par, are on level. It is very difficult to find any region in the world where consumption patterns are similar.

Another point which has been raised by the hon. members is zonal restrictions. I know many hon. members of this House are agitated over this issue. But may I submit that this issue was examined by the Foodgrains Policy Committee? The members who were associated with the Foodgrains Policy Committee were not politicians, they were economists, they were not persons belonging to any party. They themselves have indicated in their document, which is available to the House, that in the present situation in which India is placed today, it would be in the interest of the country if we continue to have these restrictions on movement from State to State. They have suggested that whenever any movement of foodgrains is to take place from one State to another, it should be only on State account and no private trade should be allowed to operate in the present circumstances; otherwise, the people will have to undergo more distress, there will be more suffering. This is the conclusion of the Foodgrains Policy Committee. This document was placed before the Conference of Chief Ministers. Ours is a federal structure; the Centre can formulate the policy in regard to such matters which are in the concurrent list only in consultation with the States because we have the joint responsibility. This document was placed before the Chief Ministers in November, 1966. The general consensus in that Conference was that the present arrangement should continue. After the General Elections, the political complexion in some States has changed. Naturally, we thought that it would be advantageous if we consulted the Chief Ministers again on this issue. This came up for discussion in the Conference of Chief Ministers in the month of April.

श्री मधु लिमये : किन राज्यों ने विरोध किया था, बता सकते हैं ?

Shri Annasahib Shinde: Yes; I can say. Bihar, U.P., Gujarat and West Bengal. They expressed the view that it would be better if State restrictions are removed, but even then, at the end, some of them expressed the view that if the Centre would allocate more food, then perhaps there would be no further complaint; they made a demand that the State restriction should be removed. But, by and large, all the other Chief Ministers expressed the view that, as far as trade between one States is concerned, it should be on State account and the present State restrictions should continue. So, we were guided by the general consensus, and we had to announce on that basis that the present arrangement would continue.

[Shri Annasahib Shinde]

18 hrs.

I think that we shou'd not try to make political capital out of it. As is well known, even in our ruling party, some Members hold the view that the present arrangement is not satisfactory. So, it is a matter which cuts across party lines. There are some Members who have honestly felt that it is not satisfactory. But I would submit that we should not try to make political capital out of it because we are passing through a very difficult situation and the only way, as I see it, out of the situation is to increase production.

श्री मधु लिमये : खेती दाम कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं की गई ?

Shri Annasahib Shinde: We shall definitely consider the suggestion of the hon. Member whether they can be published.

श्री मधु लिमये : यह ताज्जुब की बात है कि हमको यह कहने की जरूरत पड़ती है।

Shri S. S. Kothari: What about the commitment to the States?

Shri Annasahib Shinde: It would depend upon the availability of foodgrains. After all, food grains do not fall from the sky.

Shri S. S. Kothari: Has he assessed the situation? What is his reading of it? Has he made any tentative reading of it?

Shri Annasahib Shinde: We have such a large-scale public distribution system in our country. We have a network of fair price shops. In fact, the Centre is trying to see that as far as possible, within the availability, the needs of the various States are looked into and met, and this position has been explained by the hon. Minister in this House several times.

Shri S. S. Kothari: Now, there will be a detour of the ships round the Cape of Good Hope.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को कह दें कि वह खेती दाम कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित करें या सदन के टेबल पर रखें ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister has already said that he would consider the suggestion.

Shri Annasahib Shinde: There was a reference to wholesale trade. Our policy in regard to this is well known, namely that we want that in the days to come, the food trade comes more and more in the public sector, and we have established . . .

Shri Jagjiwan Ram: Let the State Governments procure more and more of the surplus. We would have no objection.

Shri Annasahib Shinde: The Food Corporation has been established for that very purpose. We only wish that the State Governments would take adequate steps to procure more and to see that private trade is banned, and if they do so we shall support them. This position has been repeatedly explained in this House as well as outside. We shall give all co-operation to the State Governments if they really go in a big way to have the maximum procurement, to adopt anti-hoarding measures and to have food in the public sector.

श्री मधु लिमये : दामों का फर्क भी घटाया जाये । इस समय बहुत फर्क है ।

18.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June 8, 1967/Jyaistha 18, 1889 (Saka).